अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आड़ में भी धार्मिक ध्रुवीकरण की घिनौनी कोशिश

एएमयू में रिपब्लिक टीवी और आरएसएस के गुर्गों ने रची साजिश

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

अलीगढ़: हिंदी में नए आए रिपब्लिक टीवी को स्थापित करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आड़ लेने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। अलीगढ़ पुलिस ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई विडियो फुटेज नहीं है, जिससे यह साबित किया जा सके कि एएमयू के उन 14 छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। अलीगढ़ पुलिस ने मीडिया को बताया कि हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिस नेता के कहने पर एफआईआर दर्ज की थी, वो भी ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर सके।

क्या घटना हुई थी

आरएसएस और भाजपा के दलाल अरणब गोस्वामी अब हिंदी में रिपब्लिक टीवी लेकर आए हैं। इस चैनल के मालिक भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर हैं। हिंदी वाले रिपब्लिक टीवी को स्थापित करने और उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर पैदा करने के लिए सबसे आसान था हिंदू-मुस्लिम विवाद खड़ा करना। रिपब्लिक टीवी के कैमरामैन और पत्रकार वहां पहुंचकर एक न्यूज बनाते हैं कि एएमयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना आम बात है और ऐसा रोज होता है। उन्होंने एक विडियो जोड़तोड़ कर बनाया और उस आधार पर भाजपा की युवा शाखा के नेता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अलीगढ़ पुलिस रिपब्लिक टीवी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया (भारतीय गणराज्य) मान बैठी और चुपचाप केस दर्ज कर लिया।

इसके बाद रिपब्लिक टीवी की टीम ने दोबारा एएमयू में जाकर रिपोर्ट बनानी चाही लेकिन एएमयू के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी शूटिंग बंद कर दी क्योंकि रिपब्लिक टीवी के पास एएमयू कैंपस में किसी भी तरह की शूटिंग की अनुमति नहीं थी।

कलई खुली

एएमयू में रिपब्लिक टीवी की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश गुरुवार को हो गया। मीडिया के सवालों के जवाब में अलीगढ़ पुलिस ने माना कि हमारे पास एएमयू के 14 छात्रों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने फिर देशद्रोह का मुकदमा कैसे दर्ज किया, इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई थी, इसलिए दर्ज किया लेकिन जिस नेता ने शिकायत दी थी, उसने भी कोई सबूत हमें नहीं सौंपा।

अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुलहरि ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, घटना के संबंध में अब तक एकत्रित किसी भी प्रमाण से छात्रों पर लगा देशद्रोह का आरोप साबित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में अभी और सुबूत इकट्ठा कर रही है।

जेएनयू के मामले में सरकार आज तक क्या साबित कर पायी ? एएमयू में भी यही खेल हो रहा है।

अगर देशद्रोह के आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो मुकदमे में इससे संबंधित धारा को हटा दिया जाएगा.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (AMUTA) ने छात्रों के खिलाफ "देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप" की निंदा की और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को इस बारे में लिखा। इसने कोविंद को संज्ञान लेने और "एक मजबूत संदेश भेजने के लिए कहा कि राजद्रोह के आरोपों को पूरी जांच के बाद ही सुना जाना चाहिए और कथित घटना के कुछ घंटों के भीतर सुनवाई पर नहीं"।

एएमयू स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कोविंद को पत्र भी लिखा। कोविंद को लिखे पत्र में कहा गया है, एएमयू पर दक्षिणपंथी ताकतों और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा झूठे आरोप लगाने के इरादे से बार-बार हमले हुए हैं। देशद्रोह सहित सात गंभीर अपराधों के आरोप में चौदह छात्रों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इसने AMU के छात्रों को 'आहत' और 'नाराज' कर दिया है। विश्वविद्यालय को 'महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है और इसके छात्र हमेशा देश के लिए खड़े हुए हैं। देश के प्रति हमारी निष्ठा पर बार-बार सवाल उठाना न केवल छात्रों के लिए बल्कि संविधान का भी अपमान है।

बचकाना आरोप

भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी की तहरीर पर एएमयू के 14 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह और हत्या के प्रयास के आरोप में पिछले मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया था। लोधी ने तहरीर में आरोप लगाया था कि वह एएमयू परिसर से सटे इलाके से गुजर रहे थे, तभी एएमयू के छात्रों की अराजक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और देश विरोधी नारेबाजी करते हुए उन पर हमला किया।

एएमयू के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि लोधी ने पिछले हफ्ते एएमयू के कुलपति को धमकी दी थी कि अगर अगले 15 दिन के अंदर उन्होंने एएमयू परिसर में एक मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं दी तो वह खुद ही निर्माण कार्य शुरू कर देंगे।

इस बीच, छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे एएमयू छात्र संघ के नेताओं ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति की तहरीर पर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जो खुद परिसर का माहौल खराब करना चाहता है। अफसोस की बात तो यह है कि इस मामले में उसके खिलाफ दर्ज शिकायत पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

सवाल यह है कि बिना किसी सबूत के पुलिस ऐसे कैसे देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को देशद्रोह के मुद्दे पर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित फ़ैसले की कोई जानकारी नहीं है? जानकारी न हो, ऐसा सम्भव नहीं क्योंकि जेएनयू मामले में देश भर में इस बात की व्यापक चर्चा हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह को कैसे परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट की उस परिभाषा के अनुसार यदि इन छात्रों ने वास्तव में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये भी होते, तब भी इनके खिलाफ़ देशद्रोह का मामला नहीं बन सकता था।

सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की अवहेलना कर रही है? साथ ही सवाल यह भी है कि भारत में अंग्रेज़ी राज स्थापित करने और उसके खिलाफ़ किसी तरह के विद्रोह की कोशिश को सख़्ती से कुचलने के लिए 1870 में लागू किया गया क़ानून आज कितना ज़रूरी है?

घिनौनी साजिशों का जवाब कौन देगा

सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वह कौन सी ताकते हैं जो जेएनयू के बाद अह एएमयू को बदनाम करने की घिनौनी साजिश रच रही है। हैरानी है कि इस देश का अमन पसंद नागरिक इस साजिश को होता हुआ देख रहा है और चुप है। इस सारे मामले में मुसलमान सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि वे नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ऐसी घटनाओं की आड़ में माहौल को हिंदू-मुसलमान होने दें और भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण की घिनौनी साजिश कर सके। लेकिन इस देश के अमनपसंद लोगों को इसका विरोध तो जरूर करना चाहिए।

आखिर जेएनयू के मामले में आज तक सरकार क्या साबित कर पाई। छात्र नेता कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत तमाम छात्र नेताओं पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए राष्ट्रद्रोह के आरोप को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। जेएनयू के मामले में भाजपा की मदद से राज्यसभा सांसद बने सुभाष चंद्रा के न्यूज चैनल ज़ी टीवी ने माहौल को जहरीला बनाने की कोशिश की थी। अब वही काम दलाल अरणव गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी चैनल कर रहा है। लेकिन एएमयू ने उस साजिश को फिर से फेल कर दिया।

जुए-सट्टे का खेल पुलिस का है पूरा घालमेल, कानून व्यवस्था हो रही फेल

फरीदाबाद (म. मो.)। दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध-चोरी, डकैती रेप व हत्या आदि की वारदातें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उससे स्पष्ट है कि पुलिस एवं कानून का कोई खौफ अपराधियों में रहा नहीं। पुलिस चौकी व थानों के निकट तो क्या पुलिस की मौजूदगी में भी अपराध करने से अपराधी अब घबराते नहीं।

अपराधी पुलिस से डरें भी क्यों जब उन्होंने पुलिस के साथ लेन-देन के संबंध बना लिये हों। ऐसे संबंधों की शुरूआत जहां छोटे-मोटे अपराधों से होती है वहीं बड़े अपराधी भी इन्हीं नर्सरियों में पैदा होते और पनपते हैं। इस शहर के खास कर एनआईटी क्षेत्र में हर तरह का जुआ- कैसीनो, चक्री आदि व सट्टा गली-गली में खुले आम चल रहा है। शराब तस्कर घर-घर शराब की सप्लाई ठेके से भी सस्ते दामों पर कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि यह सब चोरी-छिपे न होकर खुलेआम हो रहा है।

छोटे-छोटे स्कूली बच्चे तक भी गली में बैठे सट्टेबाजों से, अपने जेब खर्च के 10-20 रुपयों तक की पर्ची कटवा लेते हैं या चक्री और कैसीनो पर दाव लगा लेते हैं, चस्का पड़ने पर और पैसों का जुगाड़ करने के लिये हर गलत काम करने पर उतारू हो जाते हैं, रिक्शा वाला जल्द अमीर बनने के लालच में आकर अपने खून पसीने की कमाई को इस धंधे में झोंक देता है। समझा जा सकता है ऐसे में उसके परिवार पर क्या बीतती होगी।

इन धंधों में लगे धंधेबाजों से चौकी थाने वाले तो वसूली करते ही है तमाम सीआईए चौकियों वाले भी वसूली करने पहुंच जाते हैं। किसी जमाने में इस तरह की वसूली एसएचओ की नजर बचाकर सिपाही-हवलदार तो कर लिया करते थे लेकिन समय के साथ-साथ एसएचओ तक भी सीधे वसूली करने लगे। अब जब इलाके के एसीपी व डीसीपी भी डूबने लगें तो फिर सिपाही-हवलदार से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। आमतौर पर एसीपी व डीसीपी यह वसूली अपने रीडर के माध्यम से करते रहे हैं, परन्तु अब तो नौबत यहां तक आ गयी है कि ये अधिकारीगण सीधे ही धंधेबाजों को फोन पर रिमाईडर देकर मांग करने लगे हैं।

समझने वाली बात यह है कि जिन सुपरवाइजरी अफ्सरों का यह हाल हो, जिनका खुद इतना पतन हो चुका हो तो वे अपने मातहतों की क्या निगरानी करेंगे? जो खुद काणे हो चुके हैं उन अफसरों की मातहत भी क्यों परवाह करने लगे, वास्तव में यही वे हालात हैं जिनके चलते पुलिस महकमे का बेड़ागर्क हुआ पड़ा है। कोई अपराधी इनकी परवाह नहीं करता क्योंकि उसने थाह ले रखी है औकात पहचान ली है। इसी का परिणाम हे जो अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम अपराध करने से नहीं घबराते।

फरीदाबाद की जनता को मैडिकल कॉलेज की 'सौगात'....

पेज एक का शेष

वहीं शक्तियां आज भी इसकी राह में रोड़े बनी हैं

एक लाख करोड़ के खजाने पर कुंडली मारे बैठे मोदी सरकार के यही अधिकारी इस कॉलेज एवं अस्पताल की राह में रोड़े अटकाने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। उनका भरसक प्रयास रहा कि यहां एमआरआई सीटी स्कैन न लग पाये। एक्स-रे मशीन व अल्ट्रासाऊंड मशीन भी बड़े रो-पीटकर लगाई वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लग पाई। अल्ट्रासाऊंड के लिए अब भी एक-एक महीने की प्रतीक्षा चल रही है। जैसे-तैसे करके दिसम्बर 2018 के अन्तिम पखवाड़े में एमआरआई व सीटी स्कैन लग पाये।

फिजूल खर्चियों के लिए बेशक ईएसआईसी के पास धन की कमी न हो लेकिन उक्त उपकरणों को खरीदते समय सस्ते से सस्ता यानी पुरानी तकनीक के खरीदते हैं जबकि खरीदा जाना नई से नई आधुनिक तकनीक का चाहिए। ऐसा इसलिये हो रहा है कि मोदी सरकार ने यह अधिकार उन मूर्खो एवं धूर्तो को दे रखा है जिन्होंने 25-30 वर्ष पहले एमबीबीएस की डिग्री लेकर कॉलेज को नमस्ते कर दी थी। उन्हें खुद का ज्ञान तो नहीं दूसरों से ज्ञान लेने में अपनी बेइज्जती समझते हैं।

मूर्ख तो इतने हैं कि एमआरआई व सिटी स्कैन को पीपीपी मोड में चलाने का भरसक प्रयास करते रहे। 4 साल तक पूरी तरह असफल होने के बाद ही इन उपकरणों को खरीदा गया। उन्हीं मूर्खो ने आईसीयू व डायलसिस को पीपीपी मोड में ठेके पर दे दिया। फिलहाल आईसीयू तो बीते छह माह से बंद पड़ा है क्योंकि ठेकेदार छोड़कर भाग गया और डायलेसिस में कभी भी कोई बड़ा कांड होने के बाद यह भी बंद होना तय है।

फिलहाल 510 बैड के इस अस्पताल की पूरी क्षमता 580 जमा 220 बैड की है। 220 में कैजुअलटी आईसीयू, लेबर रूम, ओटी (आपरेशन थियेटर) आदि के बैड होते हैं जबकि शेष बैड वार्डों में होते हैं। इसी अस्पताल में जब 200 बैड में से एक चौथाई भी नहीं भरते थे अब लगभग सारे बैड फुल रहने लगे है। सर्जरी व हड्डी विभागों में एक से दो माह की प्रतीक्षा चल रही है। क्योंकि छोटे-बड़े 13 ओटी तो बनकर तैयार खड़े हैं परन्तु चालू केवल 4 हैं और वे भी केवल दिन में। यदि बेहोशी वाले डाक्टर एवं अन्य स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हो तो ये सभी 13 के 13 ओटी चौबीसों घंटे चलाये जा सकते हैं ऐसे में अभी ऑपरेशन के लिए मरीजों को जो दो-दो माह की तारीख दी जा रही है वे सब तुरन्त निपटाये जा सकेंगे।

फिलहाल काम में आ रहे 510 बैड के लिये ईएसआई नियमावली के अनुसार 500 नर्सो की आवश्यकता है जबकि कार्पोरेशन ने केवल 247 पद ही स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन उनमें से भी काफी रिक्त हैं जिन्हें ठेकेदारी के आधार पर भरने का सिलसिला जारी है। इन 247 नर्सों में, नियमानुसार जितनी स्टाफ नर्स व नर्सिंग सिस्टर का अनुपात होना चाहिए। उनका भी घोर उल्लंघन किया जा रहा है। प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक लैब टैक्नीशियन व 30 सहायकों के पद तो स्वीकृत हैं परन्तु आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। कार्पोरेशन मुख्यालय में बैठे निम्न सोच समझ के अधिकारियों के चलते फैकल्टी एवं डाक्टरों के स्वीकृत पद कभी भी भर नहीं पाते। इन्हीं नीतियों के कारण कई एसोसिएट प्रोफेसर नौकरी छोड़कर अन्यत्र संस्थानों में चले गये तथा अन्य जाने वाले हैं। मुख्यालय में बैठे अफसरों को यह समझ ही नहीं कि नौकरी छोड़कर जाने वाले विशेषज्ञों को कैसे रोक कर रखा जाये।

दफ्तरी स्टाफ के 200 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 150 खाली पड़े हैं। इसके चलते मरीजों की सेवा के लिये भर्ती नर्सिंग अर्दली दफ्तरी काम पर लगाये जाते हैं। इसके अलावा डाक्टरों को अपने असल काम को छोड़कर फाईलों से जूझना पड़ता है।

ऐसी और भी अनेकों समस्यायें हैं जो केवल मूर्ख अफसरों ने इस अस्पताल पर जबरन थोप रखी हैं। इस तथाकथित लोकार्पण के जश्न में शामिल होने को आये तमाम स्थानीय भाजपाई राजनेताओं ने कभी जानने व सुलझाने का प्रयास नहीं किया। इन नेताओं का एक मात्र लक्ष्य तो केवल इतना रहता है कि अस्पताल प्रशासन उनकी सिफारिश के आधार पर उनके प्यादों को नौकरी पर लगा ले अथवा अस्पताल से कोई व्यापारिक संबंध (ठेके आदि) बन जायें जिससे उन्हें भी कुछ चंदा आदि मिलता रह सके।

भाजपा विधायक मूलचंद ने घर के निकट स्थित सैक्टर 8 का ईएसआई अस्पताल, जिसे चलाने का पूरा दायित्व हरियाणा सरकार का है, जबकि खर्चो का 88 प्रतिशत ईएसआई कार्पोरेशन को वहन करना होता है, के भीतर झांकने तक की जरूरत नहीं समझी कि वहां कैसे उनके क्षेत्रवासियों की दुर्गति हो रही है।

ईएसआई द्वारा भेजे मरीजों की एशियन जैसे निजी अस्पतालों में होती है दुर्दशा

फरीदाबाद (म. मो.) मजदूरों के वेतन का साढ़े छह प्रतिशत वसूलने के एवज में ईएसआई कार्पोरेशन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने बीमाकृत मजदूरों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। परन्तु अपने खुद के अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाओं के चलते कार्पोरेशन ने कुछ निजी अस्पतालों को पैनल पर रखा हुआ है। इन्हीं में से एक अस्पताल है एशियन।

दिनांक 5 फरवरी को 57 वर्षीय राजकुमार नामक एक कैंसर मरीज को ईएसआई एमसी अस्पताल ने एशियन अस्पताल भेजा। वहां उनको कीमोथेरेपी देकर अगले दिन अस्पताल से छुट्टी कर दी। 10 तारीख को तबीयत ज्यादा खराब हुई तो राजकुमार को पुन: ईएसआई अस्पताल की एमरजेंसी में लाया गया जहां से उन्हें फिर से एशियन अस्पताल भेज दिया गया। परन्तु इस बार उन्हें अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। कई घंटे उनके परिजन उन्हें लिये अस्पताल में पड़े रहे। ईएसआई अस्पताल में भी फोन किये परन्तु किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आधी रात के करीब अस्पताल के बाउंसरों ने राजकुमार व उनके परिजनों को अस्पताल से बाहर धकेल दिया।

ऐसे में दुखी परिजन एस्कॉर्ट्स कम्पनी की एक कर्मचारी एवं हिन्द मजदूर सभा की नेता रोजी पंडित को लेकर उपायुक्त से उनके कार्यालय में मिले। सारा मामला सुनकर उपायुक्त ने ईएसआई अस्पताल के डीन से बात करके समस्या को समझा। ईएसआई व एशियन अस्पताल के बीच की पेचीदगी को समझने के बावजूद उन्होंने अपने प्रशासनिक प्रभाव से राजकुमार को एशियन अस्पताल में दाखिल करा दिया। जहां अब उनका इलाज चल रहा है।

बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि उपायुक्त महोदय अपने प्रशासनिक प्रभाव से कब-कब और किस-किस को इन निजी अस्पतालों में भर्ती करा पायेंगे? समझने वाली बात यह है कि निजी अस्पतालों के पास जब काम नहीं होता तो ये ईएसआई के साथ कम रेट पर अनुबंध कर लेते हैं परन्तु जब उनके पास मोटा पैसा देने वाले ग्राहक पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं तो ये ईएसआई से भेजे गये मरीजों को दुतकराने व जलील करते हैं। कैंसर मरीजों के मामले में निजी अस्पतालों की असल कमाई दो हजार की दवा के बीस हजार वसूलने में होती है परन्तु जब ईएसआई को यह राज मालूम हुआ तो उन्होंने अपने यहां से दवा भेजनी शुरू कर दी। जाहिर है निजी अस्पतालों ने कोई धर्मार्थ थोड़े ही खोल रखा है। उन्होंने सैकड़ों करोड़ मोटा मुनाफा कमाने के लिए ही तो लगाये हैं वे भला ऐसे घाटे का धंधा क्यों करने लगे? बात भी सही है, जब कीमो थेरेपी के लिए निजी अस्पताल डाक्टर भर्ती कर सकते हैं तो ईएसआई कार्पोरेशन को क्या मौत पड़ रही है अपने यहां डाक्टर भर्ती करने में? कहां लेकर जायेंगे मजदूरों का एक लाख करोड़ का खजाना?